

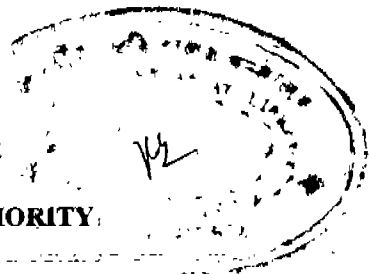


# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I  
PART I—Section 1

शासक से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 31] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 20, 1995/फाल्गुन 1, 1916

No. 31] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 20, 1995/PHALGUNA 1, 1916

श्रम मंत्रालय

मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1995

सं० यू-23013/01/95—एल डब्ल्यू.—डेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रिट याचिका सं० 2591/1994 में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 21-11-1994 के आदेश के अनुसरण में, केन्द्रीय डेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्वारा महाराष्ट्र के जिला—रायगढ़ में ब्रानागिरि, तांडे स्थित कन्टेनर फ्रेट स्टेशन में कन्टेनर की हैंडलिंग करते, भाव भाराई करने, भाव उतारने और कन्टेनर के परिवहन के कार्य (इसके बाद इसे उक्त कार्य कहा जाएगा) से डेका श्रम को समाप्त करने में संबंधित विषय की जांच करने के लिए एक लिपिकीय समिति का गठन करती है।

2. समिति का सं:5न और इसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :—

- |   |              |
|---|--------------|
| (1) श्री० शशि भूषण राव,<br>महासचिव,<br>राष्ट्रीय भारतीय रेलवे महासंघ,<br>इ रा एन०आर० रेलवेमेन्स यूनिट-2,<br>गार्डन रोड, कलकत्ता       | सदस्य        |
| (2) श्री आर०ए०पी० सिंह,<br>निदेशक (पी एण्ड आई आर)<br>कोल इंडिया लि०,<br>10—नेताजी सुभाष रोड,<br>कलकत्ता-700001                        | सदस्य        |
| (3) उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय),<br>भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान,<br>काम्पलेक्स, एल०बी०एस० मार्ग०<br>कुरला (प०),<br>बम्बई-400070 | सदस्य—संयोजक |

#### विचारार्थ विषय

“महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ में मवाशिवा में द्रोनागिरि, नोडे स्थित केन्द्रीय वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के कंटेनर फ्रेट स्टेशन में कंटेनर की हैंडलिंग करने, माल भराई करने, माल उतारने आर कंटेनर के परिवहन से संबंधित कार्य में टेका श्रम पद्धति के क्रियाकलाप का अध्ययन करना और टेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए इस बात के लिए समुचित सिफारिश करना कि क्या महाराष्ट्र के जिला रायगढ़ में द्रोनागिरि नोडे स्थित उक्त कंटेनर फ्रेट स्टेशन में टेका श्रम के नियोजन को समाप्त कर दिया जाए अवकाश नहीं।”

3. समिति का मुख्यालय बम्बई में होगा। समिति अपनी रिपोर्टें हर हाल में तीन महीने के अन्दर देगी।

एस०एस० शर्मा, महानिदेशक (श्रम कल्याण),

संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

## RESOLUTION

New Delhi, the 20th February, 1995

No. U-23013/1/95-LW.—In exercise of power conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and in pursuance to the order of 21-11-1994 of the Hon'ble Bombay High Court in Writ Petition No. 2991 of 1994, the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Tripartite Committee to go into the question of abolition of contract labour in the work of handling, stuffing, destuffing and transportation of containers to and from the Container Freight Station (C.F.S.) Dronagiri, Node in Raigad District (hereinafter the said work) Maharashtra.

2. The composition of the committee and its terms of reference will be as under :—

- (1) Ch. Shashibhushana Rao,  
Central Secretary, National Federation  
on Indian Railways,  
C/o S. R. Railwaymen's Unit-2,  
Garden Reach, Calcutta. —Member
- (2) Shri R. A. P. Singh,  
Director (P&IR),  
Coal India Ltd.,  
10—Netaji Subhash Road,  
Calcutta-700001. —Member
- (3) Deputy Chief Labour Commissioner (C),  
Indian Institute of Workers'  
Education Complex, Lal Bahadur  
Shastri Marg, Kurla (W),  
Bombay-400070. —Member-Convenor

## Terms of Reference

“To study the working of contract labour system in the work of handling stuffing, destuffing and transportation of containers to and from the Container Freight Station (C.F.S.) of the Central Warehousing Corporation at Dronagiri, Node in Nhava Sheva, Raigad district of

Maharashtra and keeping in view of the provisions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, to make suitable recommendation whether or not the employment of contract labour in the said Container Frieght Station at the Drona-giri Node, Nhava Sheva District Raigad, Maharashtra should be prohibited.”

3. The headquarters of the Committee will be at Bombay. The Committee would submit its report within three months without fail.

S. S. SHARMA, Director General (Labour Welfare)|Jt. Secy.